दैनिक जागरण
सेवा ही मानव जीवन का सौंदर्य और शृंगार है

गरीबों की भलाई

किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश भर के गरीब किसानों के मन में एक उम्मीद जगाने और उन्हें सहारा देने वाली है। गोरखपुर में इस योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने यह जो कहा कि राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना, बस ईमानदारी से सही सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंप देना है, उस पर उन्हें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह बात इसलिए कहनी पड़ी, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें इस योजना के प्रति अपेक्षित गंभीरता का परिचय नहीं दे रही हैं। यह अगंभीरता महज राजनीतिक संकीर्णता ही नहीं, गरीब किसानों की अनदेखी भी है। यह खेद और लज्जा की बात है कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी ही संकीर्णता का परिचय गरीबों को एक बड़ी राहत देनी वाली आयुष्यमान भारत योजना के प्रति भी दिखा रही हैं। इस योजना के तहत गरीबों का पांच लाख रुपये तक का उपचार मुफ्त हो रहा है। चंद महीनों में ही लाखों निर्धन इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इस योजना को अपनाने से बच रही हैं। समझना कठिन है कि कुछ राज्य सरकारें अपने लोगों को इस उपयोगी योजना से क्यों वंचित करना चाहती हैं? एक ओर तो वे दिन-रात गरीबों की चिंता में घुलती दिखती हैं और दूसरी ओर जब उनके लिए कुछ करने का अवसर आता है तो राजनीतिक द्वेषवश आनाकानी करने लगती हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की सरकार भी है जो राज्य अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटी जोत वाले किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये दिए जाने हैं। गत दिवस प्रधानमंत्री ने एक साथ करीब एक करोड़ किसानों के खाते में इस योजना की पहली किस्त भेज दी। निःसंदेह यह एक तर्क है कि छह हजार रुपये की सालाना सहायता राशि कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यह राशि जिन गरीब किसानों के पास जानी है उनके लिए बहुत मायने रखती है। निर्धन किसान इस राशि का इस्तेमाल अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।

देश में गरीबी की हालत को देखते हुए जरूरी केवल यह नहीं है कि राज्य सरकारें गरीबों के कल्याण की हर केंद्रीय योजना को सही तरह अपनाएं, बल्कि यह भी है कि इसे सुनिश्चित करें कि गरीब तबका अपने हितों के लिए और अधिक जागरूक हो। निर्धन वर्ग के लोगों को अपनी सेहत से लेकर अपने बेहतर भविष्य के लिए किस तरह और सजग होने की जरूरत है, इसे बयान कर रही हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम की वे घटनाएं जिनमें जहरीली शराब पीने के कारण तमाम लोग मर गए। ऐसी घटनाएं देश के किसी न किसी हिस्से में रह-रह कर होती ही रहती हैं। ये घटनाएं यही बताती हैं कि एक तो गरीबों के हितों की रक्षा के प्रति उपेक्षा भाव है और दूसरे, इस तबके के लोग अपने भले-बुरे की चिंता सही तरह नहीं कर रहे हैं। यह समय की मांग है कि देश के हर गरीब की चिंता कर रही केंद्र सरकार यह भी देखे कि राज्य सरकारें अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाएं।

सीट बंटवारे पर खींचतान

लोकसभा चुनाव की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में इस बार चतुष्कोणीय लड़ाई होने की संभावना है। भाजपा सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस भी सभी सीटों पर उम्मीदवार देगी। कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह भी माकपा के साथ तालमेल कर सभी सीटों पर प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वाममोर्चा और कांग्रेस में तालमेल नहीं भी होता है तो दोनों में 'दोस्ताना लड़ाई' होगी, जो भाजपा और तृणमूल के खिलाफ मानी जाएगी। कांग्रेस वाममोर्चा के साथ चुनावी तालमेल करना चाहती है। वाममोर्चा का नेतृत्व करने वाली माकपा भी इसकी इच्छुक है, लेकिन मुश्किल यह है कि वाममोर्चा में सहमति बनने के बाद ही माकपा कांग्रेस के साथ तालमेल के मुद्दे पर बातचीत कर सकती है। माकपा ने वाममोर्चा के प्रमुख घटक दलों के साथ प्रारंभिक चर्चा की तो इसपर सहमति नहीं बनी। वाममोर्चा के कुछ घटक दल कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। भाकपा, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने दो-टूक कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। वाममोर्चा को भाजपा और कांग्रेस के साथ समान दूरी बनाकर चलना होगा। इस मुद्दे पर फिर सोमवार को वाममोर्चा की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर 27 फरवरी को चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई है। वैसे माकपा ने स्पष्ट किया है कि वह इस बार 20 सीटों पर ही लड़ना चाहेगी। शेष 22 सीटों पर वाममोर्चा के घटक दल अपनी पसंद के अनुसार लड़ेंगे। अंत में जो सीटें शेष बचेंगी, उसी पर माकपा कांग्रेस के साथ तालमेल करना चाहेगी। यहां मामला सीटों की संख्या को लेकर नहीं, बल्कि पसंद को लेकर है। माकपा अपनी पहली पसंद वाली सीटों पर लड़ना चाहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर वाममोर्चा के घटक दल भी सहमत होंगे। इसी तरह यह जरूरी नहीं कि कांग्रेस भी माकपा और वाममोर्चा के घटक दलों की पसंद की सीटें देने पर सहमत हो जाए।

उदारवादियों का अनुदार चेहरा

हृदयनारायण दीक्षित

आतंक के प्रति हमदर्दी जताने वाले युवकों की बात तो चिंताजनक है ही, लेकिन ज्ञान संपन्न होने के बावजूद राष्ट्रहित की अनदेखी छोटा अपराध नहीं है

विचार विविधता भारत की प्रकृति है। यहां ऋग्वैदिक काल में भी विचार विविधता थी। आधुनिक भारत में भी विचार स्वातंत्र्य है, लेकिन राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सर्वोपरि हैं। संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में 'भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा' के बंधन हैं, लेकिन भारत के कथित उदारपंथी लिबरल इस मर्यादा का पालन नहीं करते। वे भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के प्रति अनुदार रुख अपनाते हैं। इस वर्ग के लेखक-स्तंभकार राष्ट्रीय व्यथा के अवसरों पर भी शांत चित्त विचार नहीं करते। राजनीतिक दलतंत्र का भी एक वर्ग राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की मर्यादा का उल्लंघन करता है। बेशक दलतंत्र को सरकार की प्रशंसा या आलोचना का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय व्यथा के अवसरों पर शब्द प्रयोग की सुनिश्चित मर्यादा है। पुलवामा हमले से समूचा भारत व्यथित है। आमजन तिरंगा लेकर आंसू बहाते सड़कों पर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित और संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को इसकी गंभीरता से अवगत कराया। पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित यह हमला राष्ट्रीय बेचैनी की शीर्ष प्राथमिकता है। फिर भी राष्ट्रविभाजक टिप्पणियां हो रही हैं। शत्रु देश को लाभ पहुंचाने वाले वक्तव्य भी आए हैं।

सीआरपीएफ देश का प्रतिष्ठित सुरक्षा बल है। एक पत्रिका ने पुलवामा में शहीद इस बल के जवानों का जातीय विश्लेषण किया है कि शहीदों में अधिकांश निचली जातियों के हैं। सीआरपीएफ प्रमुख दिनकरन ने रिपोर्ट की निंदा करते हुए कहा है कि 'रिपोर्ट शहीदों का अपमान है। शहीद जातिगत आंकड़ा नहीं है। जवान स्वयं को सिर्फ भारतीय जानते हैं।' उदारवादियों की अभिव्यक्ति राष्ट्रीय एकता की शत्रु है। वे घटना के बाद सड़कों पर निकले व्यथित 'भारत के लोगों' का भी जातिगत प्रतिशत निकाल रहे होंगे। ऐसा जनज्वार किसी दल द्वारा प्रायोजित नहीं हो सकता। यह स्वतः स्फूर्त, स्वयं प्रेरित है। जनता व्यथित और आक्रोशित है। विपक्ष के एक नेता ने पुलवामा को भारत की आत्मा पर आक्रमण बताया था, लेकिन उसी दल के प्रवक्ता ने केंद्र पर उन्मादी राष्ट्रवाद फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने भी चुनावों के मद्देनजर भारत पर ऐसा ही आरोप लगाया है। अफसोस है कि उदारवादियों एवं राजनीतिक बयानों के संदर्भ पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने वाले हैं।

सरकारों पर टिप्पणी विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यह सरकारी आलोचना तक ही सीमित होनी चाहिए। इस सीमा के पार की गई आलोचना शत्रु देश को लाभ पहुंचाती है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं। उनके विरुद्ध पाकिस्तान में जासूसी के आरोप हैं। मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में है। पाकिस्तान के अनुसार उसने भारतीय मीडिया में प्रकाशित अंशों को साक्ष्य बनाया है। शत्रु देश के मंसूबों को फायदा पहुंचाने वाली ऐसी रिपोर्ट भारत हितैषी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पाकिस्तान परस्त सवाल उठाए कि 'चुनाव के ठीक पहले ही ऐसा हमला क्यों हुआ?' यह राष्ट्रविरोधी और पाकिस्तान हितैषी बयान है। जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। हमला पाकिस्तानी सेना की शह पर जैश ने किया, लेकिन देश के एक बड़े अखबार में छपा कि घटना कश्मीर के स्थानीय लोगों की करतूत है। चिंतक, लेखक और विश्लेषक होना आदर योग्य है, लेकिन राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होना कैसा उदारवाद है? दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। ऐसा 'उदारभाव' केवल भारत में ही दिखाई पड़ता है।

भारत ने व्यथित होकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सैनिक जान हथेली पर लेकर उस अभियान में भागीदार बने। यह सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का अवसर था। देश के आमजनों को सेना के प्रति गर्व था, लेकिन दलतंत्र सर्जिकल स्ट्राइक के सुबूत मांग रहा था। इसी तरह पाकिस्तान भी लक्षित हमले के सुबूत मांग रहा था। कुछ टिप्पणीकार भी पाकिस्तान की तर्ज पर साक्ष्य मांग रहे थे। पाकिस्तान के विरुद्ध व्यापक जनाक्रोश है। भारतीय मीडिया ने सुरक्षाबलों पर कश्मीरी युवकों द्वारा पत्थरबाजी की घटनाएं दिखाई हैं। ऐसे कश्मीरी युवकों के प्रति भारत में स्वाभाविक गुस्सा है। देश के कुछ भागों में निर्दोष कश्मीरी युवकों के साथ दुर्व्यवहार की भी घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं भारतीय जन की प्रकृति नहीं हैं। वे अपवाद हैं और अपवाद स्वाभाविक नियम नहीं होते। इन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किया जा रहा है। राष्ट्रीय व्यथा और चिंता के समय समाज के सभी वर्गों को एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता होती है। विचार प्रकट करने और लोकमत बनाने वाले स्तंभकारों और टिप्पणीकारों को भी राष्ट्रीय व्यथा दूर करने वाले प्रयासों में साथ रहना चाहिए। दलों ने अल्पकालिक एकजुटता दिखाई और निंदा में लग गए। चिंतनशील समूह को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए।

पुलवामा हमले से उपजा जनाक्रोश भारतीय राष्ट्रवाद की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वंदेमातरम् का जयघोष और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे किसी दल या सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रवाद सकारात्मक है। यही हिंसक हमले के विरुद्ध आक्रोश में है। मोदी सरकार जनगणमन के साथ है और अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रही है। पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयास संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में उसे आतंकवादी सिद्ध कराने की कोशिशें प्रशंसनीय हैं। सिंधु जल संबंधी घोषणा भी इसी का भाग है। भारत को अजेय बनाए रखने और पाकिस्तानी रक्तचरित्र को उचित जवाब देने के लिए सरकार सक्रिय है। कहीं कोई सांप्रदायिक गोलबंदी नहीं है, लेकिन एक स्तंभकार ने लिखा है कि 'शासक पार्टी परिवार से जुड़े संगठनों ने ही इस बदले की कार्रवाई का आयोजन किया है, क्योंकि सीमापार शत्रु के अलावा राष्ट्रवादी उन्माद के लिए आसपास प्रत्यक्ष शत्रु जरूरी है। सांप्रदायिक राष्ट्रवादी उन्माद जगाने का यह खेल और भी खतरनाक है।' यह टिप्पणी पाकिस्तानी नजरिये के साथ है। लिबरल सहज राष्ट्र जागरण को सांप्रदायिक राष्ट्रवादी उन्माद बता रहे हैं।

ऐसा अक्सर होता है। उदारवादी राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक कहते हैं और बड़े आनंद से पाकिस्तान की पैरवी करते रहते हैं। मुंबई हमला भारत पर सीधा आक्रमण था। पुलवामा की तरह प्रच्छन्न युद्ध था। हमले के बाद अजीज बर्नी की किताब आई-'आरएसएस की साजिश।' कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, फिल्मकार महेश भट्ट आदि इस जलसे में जुटे। लब्बोलुआब यह था कि हमला यहां के ही लोगों ने करवाया। यह निष्कर्ष पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन बर्नी गच्चा खा गए। पाकिस्तान ही वास्तविक गुनहगार निकला। मुंबई हमला भुलाने की कोशिश के बावजूद नहीं भूलता। पाकिस्तानी आतंकवाद का दर्द भारत की राष्ट्र देह को प्रतिपल कष्ट देता है। बहुत सारे लोग उससे पगार लेते हैं। आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं। आत्मघाती बनते हैं, लेकिन कुछ लोग आतंकी बने बिना ही उसके पक्ष में बोलते लिखते हैं। वे उदारवादी कहलाते हैं। वे स्वयं को लिबरल, सेक्युलर, वैज्ञानिक भौतिकवादी वगैरह कहते हैं। इससे राष्ट्रहित की क्षति होती है। राष्ट्रीय एकता-अखंडता पर चोट होती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इसे 'प्रज्ञा अपराध' कहा गया है। अबोध युवकों की बात तो चिंताजनक है ही, लेकिन ज्ञान संपन्न होने के बावजूद राष्ट्रहित की अनदेखी छोटा अपराध नहीं है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आतंक पर अंकुश का स्थायी उपाय

जेकेएस परिहार

कश्मीर में आतंकवाद तभी समाप्त होगा जब आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान से पोषित होने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं

पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में राष्ट्रभक्ति की भावना चरम पर है। लोग 'अभी नहीं तो कभी नहीं' की तर्ज पर पाकिस्तान से जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए बेसब्र हैं। कश्मीर समस्या के दीर्घकालिक समाधान और पाकिस्तान को सही सबक सिखाने का यह उपयुक्त समय है। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद तथा पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठ एवं हमले स्वतंत्रता के समय से ही शुरू हो गए थे। कश्मीर के तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह के ढुलमुल रवैये तथा दो देशों के बीच एक बफर राष्ट्र के रूप में रहने की उनकी ललक ने इसे और हवा दी। वहीं कश्मीर में कबायलियों के वेश में पाक अस्थिरता को बढ़ावा देता रहा। 22 अक्टूबर, 1947 को पाक सेना ने हमला बोल श्रीनगर के बाहरी इलाके तक कब्जा कर लिया। ऐसे में हरि सिंह ने भारत से सैन्य हस्तक्षेप की मांग की। भारत ने राज्य के पूर्ण विलय के बाद ही सैन्य हस्तक्षेप की शर्त रखी। महाराजा ने कश्मीर पर पाकिस्तान के संभावित कब्जे को भांपते हुए 26 अक्टूबर, 1947 को जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए।

इसके बाद भारतीय सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कश्मीर घाटी के तीन चौथाई भाग और लद्दाख के कुछ हिस्सों से घुसपैठ करने वाली पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। हालांकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दूरदराज के हिमाच्छादित क्षेत्रों, समयाभाव तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से हुए युद्धविराम की वजह से जम्मू, कश्मीर घाटी और गिलगित बाल्टिस्तान का भू-भाग पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया। संयुक्त राष्ट्र के 1948-49 के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर समस्या के पूर्ण समाधान के लिए जनमत संग्रह करने तथा उसके पूर्व पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से अपनी सेना तथा प्रशासन हटाने और भारत को जनमत संग्रह होने तक कश्मीर में अपनी यथास्थिति तथा सेना बनाए रखने की अनुमति दी। हालांकि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की इस प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया। 1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात हुए ताशकंद समझौते और 1971 के युद्ध के बाद 2 जुलाई, 1972 को हुए शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय चर्चा के द्वारा कश्मीर समस्या का हल निकालने का उल्लेख है, परंतु पाकिस्तान ने इसका भी कभी पालन नहीं किया। जिसका परिणाम 1999 में कारगिल में घुसपैठ और तीन युद्धों में भारी पराजय से बौखलाया पाकिस्तान कश्मीर में लगातार आतंकवाद का विष फैला रहा है।

वास्तव में हमेशा बर्फ से ढंके हुए लद्दाख के उत्तरी-पूर्वी इलाके तथा पीरपंजाल के ऊंचे पहाड़ और घने जंगल आतंकवाद की समस्या से निपटने में भौगोलिक अड़चन हैं। साथ ही सीमा के दोनों ओर नागरिकों की वेशभूषा और भाषा में समानता भी आतंकवादियों को छिपने में बहुत मददगार और सैन्यबलों के लिए एक कठिन चुनौती है। इसकी आड़ में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं सीमा पार घुसपैठ और छिटपुट छद्म युद्ध में 1989 से लगातार बढ़ोतरी हुई है। सोवियत संघ-अफगानिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी आइएसआइ, तालिबान, अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों के गठजोड़ ने कश्मीर में आतंकवाद को काफी बढ़ावा दिया है। इन्हें पाक पोषित आतंकी संगठनों का भी भरपूर साथ मिला है। 1999 का कारगिल युद्ध, एयर इंडिया के विमान अपहरण की घटनाएं उस वक्त आतंकवाद की चरम अवस्था थीं। 2008 तक आतंकवाद में कुछ कमी अवश्य हुई थी, किंतु पिछले पांच वर्षों में घाटी में आतंकवाद फिर से अजगर के समान फैल चुका है। 1989 से अब तक दो लाख से भी अधिक कश्मीरी पंडित घाटी से विस्थापित हो चुके हैं। अपने ही देश में विस्थापितों की जिंदगी जीना कश्मीरी पंडितों के लिए एक भीषण त्रासदी की दुखद गाथा है।

आज कश्मीर समस्या के प्रति तात्कालिक और दीर्घकालीन, दोनों ही स्तरों पर सतत और गंभीर प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का विश्वास पूर्णरूपेण निरर्थक है। सबसे पहले पाकिस्तान से सभी प्रकार के संबंध खत्म कर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग किया जाए। हालांकि चीन उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लिहाजा भारत को ईरान, अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका और फ्रांस को साथ लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। गुलाम कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को सक्रिय और पूर्ण सैन्य कार्रवाई से मुक्त कराना भी जरूरी है। साथ ही पाकिस्तान को सामरिक और राजनीतिक दोनों ही रूप से कमजोर करने के लिए हमें बलूच आंदोलन को नैतिक, आर्थिक और सामरिक सहयोग देना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त 24 विधानसभा सीटों और लोकसभा की एक सीट के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 48 में संशोधन के द्वारा समीपस्थ इलाकों की सीटों पर एक से अधिक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जा सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 370 को पूर्ण रूप से हटाने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान को कश्मीर और बाहर भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का बिना वजह मौका मिलेगा। एक तरह से पिछले 70 वर्षों में अनुच्छेद 370 में कई संशोधनों द्वारा जम्मू-कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के अनुरूप ढाला जा चुका है। हालांकि अन्य भारतीय नागरिकों को कश्मीर में बसने और उद्योग लगाने की अनुमति अवश्य ही दी जानी चाहिए। कश्मीर के झंडे और संविधान को बनाए रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर में आंतरिक आतंकवाद तभी समाप्त हो सकता है जब आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान से पोषित होने के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। कश्मीरी जनमानस में भारत के प्रति राष्ट्रभाव तथा आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास आवश्यक हैं। हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, यह शासन और हर भारतवासी को समझना चाहिए। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की धरपकड़ में सतर्कता और सूझबूझ की जरूरत है। वहां सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या को उपयुक्त स्तर तक सीमित रखने की बहुत आवश्यकता है। सशस्त्र पुलिस बल सामान्य अवस्था में शांति और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए उपयुक्त हैं, परंतु छद्म युद्ध और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, कठोर मनोबल एवं तर्कसंगत संचालन के लिए सेना ही सार्थक एवं सर्वथा उपयुक्त है। कुल मिलाकर आज कश्मीर को उद्योग, रोजगार के अधिक अवसर, यातायात के साधन तथा उच्च शिक्षा एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता है।

(लेखक भारतीय सेना में मेजर जनरल रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेरणादायक आचरण

आज के युग में चारों तरफ चरित्र एवं नैतिक पतन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस कारण पाप कर्म बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के लिए ज्यादातर समाज के आम व्यक्ति को जिम्मेवार माना जाता है, परंतु विचार करने से ज्ञात होता है कि आज के युग में ऐसे जीवित चरित्रों की भारी कमी है जो अपने आचरण से जनसाधारण के लिए प्रेरणा स्रोत एवं प्रतीक बन सकें। ऐसा देखने में आया है कि जिन अनेक लोगों को समाज श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखता था, उन्हीं के अनैतिक तथा पाप पूर्ण आचरण से समाज में निराशा तथा कुंठा को बढ़ावा मिला है। एक आम व्यक्ति जिन्हें अपना प्रेरणादायक समझता था, उनके इस प्रकार के आचरण से वह भी अनैतिक कर्मों में लिप्त होने से नहीं चूकता है। इस प्रकार समाज का पतन होता रहता है। इस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि दूसरों को शिक्षा देने से पहले शिक्षक को स्वयं सदाचार तथा नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए। जो महान आत्मा अपने सदाचरण से जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है, उन्हें आचार्य अर्थात आदर्श गुरु कहा जाना चाहिए।

सदाचरण के उदाहरण भी हमारे देश में देखे गए हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में देश में खाद्यान्न की भारी कमी हुई थी। शास्त्री जी ने इस स्थिति से उबरने के लिए पूरे देश से सोमवार का उपवास करने का आग्रह किया जिसका वह स्वयं पालन करते थे। इसी प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के जनरल ने भी इसी प्रकार की खाद्यान्नों की कमी के समय स्वयं भी आधा भोजन करना शुरू कर दिया था। ऐसे आचरण से समाज को प्रेरणा मिलती है तथा मनोबल बढ़ता है जिससे मुश्किल समय में भी समाज संयम एवं प्रेरणा से इस प्रकार के समय से बाहर आ जाता है, जैसा कि देखा गया है!

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि धर्मगुरुओं एवं देश के शासकों के आचरण की कितनी महत्ता है। इसलिए इन पदों पर बैठे हुए महानुभावों को अपने आचरण को इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे उनके आसपास के मनुष्य उनसे प्रेरणा लेकर पाप कर्मों से बच सकें। इसलिए सर्वप्रथम यदि हमें समाज को सुधारना है तो समाज के नायकों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए उसके बाद समाज स्वयं सुधर जाएगा।

कर्नल (रिटायर्ड) शिवदान सिंह

बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी

सुनीता मिश्रा

कई ऐसे मां-बाप हैं जो बेटों को ज्यादा तरजीह देते हैं, जबकि बेटियों ने मौका मिलने पर हर बार खुद को साबित किया है

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रामगढ़ में देश के तीसरे एवं प्रदेश के पहले महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया। इससे एक पखवाड़े पहले जमशेदपुर में प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इससे बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा और महिला विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर वे अपने क्षेत्र का विकास भी कर सकेंगी।

हमारे देश में गरीब और पिछड़े राज्यों से आने वाली कई बेटियों ने बानगी पेश की है। इस साल गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के जयपुर के रहने वाले एक बस कंडक्टर की बेटी ने राजपथ पर इतिहास रचते हुए पहली महिला टुकड़ी का नेतृत्व किया। 26 जनवरी की परेड में मेजर खुशबू कंवर असम राइफल्स की महिला टुकड़ी की कमांडर थीं। 30 वर्षीय खुशबू ने उस असम राइफल्स के दल का नेतृत्व किया, जो देश का सबसे पुराना अर्द्धसैनिक बल है। वहीं झारखंड के हजारीबाग जैसे छोटे शहर से आने वाली कैप्टन शिखा सुरभि ने पूरे देश में अपना परचम लहराया। दिल्ली के राजपथ पर परेड में उन्होंने भारतीय सेना की कोर मोटर साइकिल टीम का नेतृत्व किया। वहीं हॉकी जूनियर टीम की राष्ट्रीय विजेता रहीं झारखंड की लड़कियां भी मुश्किल परिस्थितियों को पार कर समाज में सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। महिला क्रिकेट टीम भी पुरुष क्रिकेट टीम से कम नहीं है। इसके अलावा साइना नेहवाल, एमसी मैरीकॉम जैसी तमाम महिलाएं खेलों की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती रही हैं। पढ़ाई-लिखाई में तो लड़कियां लड़कों पर हमेशा से ही भारी पड़ती रही हैं। माता-पिता की गरीबी उनकी राह में कोई रोड़ा नहीं अटका पाती। अच्छी बात यह है कि सरकारें भी अब लड़कियों की पढ़ाई को तरजीह देने लगी हैं। झारखंड सरकार बेटियों की अच्छी शिक्षा के लिए कस्तूरबा विद्यालयों का संचालन कर रही है। इसके तहत यहां गरीब एवं आदिवासी बेटियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में मिल रही है। सरकार के इस कदम से झारखंड की लाखों महिलाएं आज अपने सपनों को साकार कर रही हैं। इससे उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने, आगे बढ़ने और दूसरी लड़कियों को प्रेरणा देने का मौका मिल रहा है।

बहरहाल सरकार के अलावा समाज को भी बेटियों को बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। बेटियों को घर की चाहरदीवारी और चूल्हा-चौके से बाहर निकालकर आत्मसम्मान का जीवन देना होगा। हमारे देश के कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं, जहां आज भी बेटियों की सुबह से लेकर रात तक घर के कामकाज में निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि वे पढ़ना नहीं चाहती हैं। वे अपने मन के अंदर ख्वाबों की माला पिरोती रहती हैं, लेकिन अपने घर की आर्थिक हालत और समाज के डर से घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं। उनका यह डर खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। अभी भी कई ऐसे मां-बाप हैं, जो बेटियों से कहीं ज्यादा तरजीह बेटों को देते हैं, जबकि बेटियों ने हर बार मौका मिलने पर खुद को साबित किया है। अगर उन्हें परिवार और समाज का सहयोग मिले तो वे कुछ भी कर सकती हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अब आतंक के कैंसर की सर्जरी जरूरी है

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'संकट के समय सस्ती राजनीति' में कश्मीर घाटी के जिस आतंकवाद की बात की है, वह अब कैंसर की तरह पूरी घाटी में व्याप्त हो गया है। मोदी सरकार ने जब सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के द्वारा घाटी के इस आतंकी कैंसर की सर्जरी करनी शुरू की तो पाक पोषित आतंकी प्रतिघात के रूप में भारत के नगरौटा, पठानकोट और उड़ी के सैन्य ठिकानों पर घातक आतंकी हमले किए गए। आमने-सामने के सीधे युद्ध में हमेशा मुंह की खाने वाला पाकिस्तान पिछले तीन दशकों से आतंक के जरिये भारत से छद्म युद्ध कर रहा है। भारत के कश्मीरियों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने प्रतिकार के लिए जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पोषित कर, उसके माध्यम से मुस्लिम बहुल कश्मीर में आतंक का कैंसर फैला रहा है। भारत की पिछली केंद्र सरकारों की अनदेखी के कारण आतंक का यह देशघाती कैंसर घाटी की रग-रग में व्याप्त हो गया। पुलवामा का भीषण आतंकी हमला कश्मीर घाटी की इसी आतंकी रुग्णता का दुष्परिणाम है, लेकिन इस हमले के बाद भारत में जैसा जनाक्रोश परिलक्षित हुआ, वह अभूतपूर्व है। इसके पीछे शायद वह जन-विश्वास ही है जो उड़ी हमले के बदले के रूप में मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक से पैदा हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार आतंक के बढ़ते कैंसर की सर्जरी करने के लिए कटिबद्ध है। वैसे देश के इस आतंकी रोग की सर्जरी उस समय ही हो जानी चाहिए थी जब नब्बे के दशक में कश्मीर घाटी का आतंक चरम पर था और आतंकवादियों के खूनी कहर से कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन करने को विवश हो गए थे, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार मूक होकर घाटी में कश्मीरी पंडितों का सामूहिक नरसंहार देखती रही, जिसका दुष्परिणाम संसद और मुंबई के नागरिक आतंकी हमले के रूप में देश को झेलना पड़ा। आज फिर से पुलवामा हमले को लेकर विपक्ष द्वारा जैसी सस्ती राजनीति की जा रही है, वह देश की एकजुटता को बिखेर सकती है, इस दृष्टि से सावधानी अपेक्षित है।

pandeyvp1960@gmail.com

सही कदम

हरियाणा सरकार की लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समय पूर्व सेवानिवृत्त की योजना सही है। कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर भूल जा